(b) what is the total requirement of aluminium to meet the domestic demand; and

(c) by when the country is likely to be self-sufficient in aluminium?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) The production during 1984-85 is expected to be 2,60,000 tonnes approximately.

(b) 3,10,000 tonnes is the estimated requirement during the current year.

(c) The country's present demand could be met if the installed production capacity of 3,62,000 tonnes per annum is fully utilised and adequate power is made available for the purpose.

हिन्दी सलाहकार समिति

1725. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रधानमंत्री के कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति गठित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) प्रधानमंत्री के कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग से भिन्न है । यह एक छोटा कार्यालय है जो प्रधान मंत्री को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही इस कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जारी निदेशों के क्रियान्वयन का काम इस कार्यालय के एक अपर सचिव को सौंपा गया है ।

Letters seized from the Golden Temple Complex

1726. SHRI RAMANAND YADAV:
SHRIMATI AMARJIT KAUR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two sacks full of letters which were addressed to the late Shri Bhindrawale by various people were seized after the extermists were flushed out from the Golden Temple Complex;

(b) whether a careful study of those letters has been made; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) to (c) Some documents have been recovered from the Golden Temple Complex. These are under scrutiny and no details can be given at this stage.

Review of implementation of various Tribal Development Schemes in Orissa

1727. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the implementation of various tribal development schemes in Orissa in general and Phulbani District in particular; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b) Yes, Sir. Ministry of Home Affairs review the progress in the implementation of tribal development programmes in Orissa from time to time and specially at the time of the finalisation of Tribal sub-Plan. Review of the Item No. 7 of 20-Point Programme on a monthly and quar-

terly basis is also undertaken. 21 ITDA Projects in Orissa State and 2 ITDA Projects in Phulbani District are under implementation to promote the economic well-being of the Tribal Families. District/ITDP wise review is undertaken by the State Government as per the review Scheduled Tribe Families numbering 3,56,724 have been economically assisted through the various income generating programmes, viz, ITDP Programmes, IRD Programmes and ERRP Programmes in the State up to March, 1984 during the Sixth Plan Period. Similarly, 17,206 Scheduled Tribes Families have been economically benefited through these schemes in the Phulbani District during the last 4 years.

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी का प्रयोग

1728. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र में सरकारी प्रयोग के लिये कौन-कौन सी विदेशी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं ; और

(ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र में सरकारी प्रयोग के लिये हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् जैसी एजेंसियों के काम-काज की आधिकारिक भाषायें हैं—अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश ।

(ख) कतिपय सदस्य देशों के साथ समय-समय पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किये गये हैं । स्थिति इस प्रकार है :

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र के काम-काज की आधिकारिक भाषा बनाने के लिये महासभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 163 के अधीन प्रक्रिया नियमावली के नियम 51 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखना होगा जो इनके काम-काज की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है । एक बार ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाये, जिसके बाद एक समिति प्रस्तावित संशोधन पर अपनी रिपोर्ट देगी और तब इसके लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत से अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के पश्चात् यदि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र के काम काज की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो अनुमानतः इस पर परिचालक व्यय प्रति दो वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपये आयेगा जो मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुये प्रगामी रूप से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ता जायगा । इससे संयुक्त राष्ट्र को भारत का अंशदान लगभग 200 प्रतिशत बढ़ जायेगा । उपस्कर आदि लगाने का खर्च इसके अलावा होगा । इसके अतिरिक्त कुछ आवर्ती खर्चे भी होंगे जिनके बारे में इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

Casual workers working in the Publication and Information Directorate, New Delhi

1729. SHRI RAM PUJAN PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of skilled/unskilled casual workers working in the Publication and Information Directorate, under the Department of Science and Technology who have been regularised during the last three years (Year-wise);

(b) the number of skilled/unskilled casual workers who have been working for more than three years and have not been made regular and the reasons therefor; and

(c) whether Government have formulated any time-bound programme